खिलौना उद्योग से 25% हिस्सेदारी का लक्ष्य

भारत का घरेलू खिलौना बाजार वर्ष 2034 तक 5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान : वित्त मंत्री सीतारमण

नई दिल्ली, 08 जुलाई. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को भारतीय खिलौना उद्योग से वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भारत को वर्ष 2032 तक 179 अरब डॉलर तक पहुंचने वाले वैश्विक खिलौना बाजार में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए.

उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार की संभावनाओं के साथ-साथ भारतीय उद्योग को अंतरराष्ट्रीय अवसरों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा. राष्ट्रीय राजधानी में टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल बी2बी एक्सपो 2026 को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का घरेलू खिलौना बाजार वर्ष 2034 तक करीब 5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, लेकिन उद्योग को इससे कहीं बड़े वैश्विक बाजार को ध्यान में रखकर रणनीति बनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि वैश्विक खिलौना कारोबार में भारत के लिए व्यापक अवसर मौजूद हैं और देश को अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए कड़े गुणवत्ता मानकों और नियामकीय सुधारों ने भारतीय खिलौना उद्योग को नई दिशा दी है.

उन्होंने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने निगरानी और प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत किया है, ताकि देश में केवल सुरक्षित और प्रमाणित खिलौनों की बिक्री सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कहा कि आयातित खिलौनों में भी सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है, जिससे असुरक्षित उत्पादों को भारतीय बाजार तक पहुंचने से रोका जा सके.

> रोजगार और उद्यमिता का नया क्षेत्र बन रहा खिलौना उद्योग- सरकार ने कहा कि खिलौना उद्योग अब विनिर्माण, रोजगार और उद्यमिता के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रहा है. यह क्षेत्र देशभर के कारीगरों, निर्माताओं, व्यापारियों और छोटे व्यवसायों के लिए आजीविका के नए अवसर तैयार कर रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत केवल अधिक खिलौने बनाने की दिशा में नहीं बढ़ रहा, बल्कि ऐसा मजबूत ढांचा तैयार कर रहा है जिससे गुणवत्ता, नवाचार और भारतीय पहचान वाले खिलौनों को वैश्विक बाजार में स्थान मिल सके.

नवी मुंबई हवाई अड्डे से दवाओं के आयात को मंजूरी

नवी मुंबई, 8 जुलाई. केंद्र सरकार ने दवाओं के आयात को आसान बनाने के लिए नवी मुंबई हवाई अड्डे को दवा आयात के अधिकृत प्रवेश केंद्र के रूप में अधिसूचित किया है. इस फैसले के बाद अब इस हवाई अड्डे के जरिए भी देश में दवाओं का आयात किया जा सकेगा. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवा नियम, 1945 के नियम 43ए में संशोधन कर नवी मुंबई हवाई अड्डे को अधिकृत हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया है. यह निर्णय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद लिया गया है. इस संशोधन के साथ देश में सड़क, रेल, समुद्री और हवाई मार्ग सहित दवाओं के आयात के लिए अधिसूचित प्रवेश केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 42 हो गई है.

अर्थव्यवस्था को गति देंगे डीपीआई और एआई

नई दिल्ली, 08 जुलाई. भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था देश की भविष्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मजबूत आधार बन चुकी है. राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित डिजिटल पेमेंट्स कॉन्क्लेव में विशेषज्ञों ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), डिजिटल पेमेंट और नई तकनीकों का प्रभावी उपयोग भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.

राष्ट्रीय राजधानी में चिंतन रिसर्च फाउंडेशन (सीआरएफ) ने इकिगाई लॉ और कोआन एडवाइजरी ग्रुप के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया. कार्यक्रम में सीआरएफ के सदस्य संजीव अहलूवालिया ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है. उन्होंने वित्तीय समावेशन बढ़ाने और आर्थिक दक्षता में सुधार के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पेमेंट्स की अहम भूमिका पर जोर दिया.

इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के विजिटिंग प्रोफेसर दीपक मिश्रा ने कहा कि डिजिटलाइजेशन केवल तकनीक अपनाने से संभव नहीं है. इसके लिए मानव पूंजी, संस्थागत भरोसे और लगातार निवेश की मजबूत नींव जरूरी है. उन्होंने कहा कि आज एआई का इस्तेमाल करने वाले लोग ही भविष्य के इनोवेटर बनेंगे और उभरती तकनीकों के साथ समझदारी से जुड़ना समय की मांग है.

> शव नादर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के डीन रजत कथुरिया ने कहा कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भरोसे पर आधारित है. उन्होंने कहा कि रिसर्च, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई-वैल्यू डिजिटल सेवाओं के जरिए उत्पादकता बढ़ाने की बड़ी संभावना है. हालांकि उन्होंने आगाह किया कि तकनीकी प्रगति समावेशी होनी चाहिए और इसमें पहचान की सुरक्षा, सहमति तथा एक्सेसिबिलिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए.

अहमदाबाद मंडल ने जून-2026 में वाणिज्यिक क्षेत्र में रचा नया कीर्तिमान

अहमदाबाद, 08 जुलाई. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने जून-2026 के दौरान मण्डल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश के नेतृत्व में वाणिज्यिक क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हुए माल राजस्व, पार्सल व्यवसाय, गैर-किराया राजस्व, यात्री सुविधाओं तथा टिकट जांच अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. मंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए.

माल राजस्व - जून-2026 में 606.43 करोड़ का माल राजस्व अर्जित किया गया, जो निर्धारित लक्ष्य से 3.60 प्रतिशत तथा गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13.59 प्रतिशत अधिक है. यह वित्तीय वर्ष 2026-27 का अब तक का सर्वाधिक मासिक माल राजस्व है. 30 जून 2026 को 26.58 करोड़ का एक दिवसीय माल राजस्व अर्जित कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया. पार्सल व्यवसाय- जून-2026 में 6.19 करोड़ का पार्सल राजस्व अर्जित किया गया, जो गत वर्ष की तुलना में 7.65प्रतिशत अधिक है. भुज से बांद्रा टर्मिनस तक 22 टन आम पार्सल सेवा के माध्यम से भेजा गया, जिससे एक ही दिन में 1.26 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ.यात्री व्यवसाय एवं कोचिंग - जून-2026 में 145.58 करोड़ का यात्री राजस्व अर्जित किया गया. अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए 67 विशेष रेल सेवाएं संचालित की गईं. यात्रियों की सुविधा के लिए 122 अतिरिक्त कोच लगाए गए, जिससे लगभग 0.97 लाख यात्रियों को लाभ मिला.

> **टिकट जांच एवं स्वच्छता अभियान**
> जून-2026 में टिकट जांच के माध्यम से 2.70 करोड़ की आय अर्जित की गई, जो गत वर्ष की तुलना में 23.29त्न अधिक है. स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 1,230 एंटी-लिटरिंग मामलों में कार्रवाई करते हुए 2.20 लाख का जुर्माना वसूला गया. गैर-किराया राजस्व : नई पहल- कांकारिया गुड्स शेड में एक्सेस-कंट्रोल्ड पेड पार्किंग एवं फ्रेंट एलाइड सर्विसेज के लिए 7 वर्ष की अवधि का 20.73 करोड़ मूल्य का अनुबंध प्रदान किया गया.

करुण्या यूनिवर्सिटी में 33वां दीक्षांत समारोह आयोजित

महिंद्रा एंड महिंद्रा के आर. वेलुसामी को मानद डॉक्टरेट की उपाधि

उत्कृष्ट विद्यार्थियों को चांसलर अवॉर्ड से किया गया सम्मानित

कोयंबटूर. करुण्या यूनिवर्सिटी ने 4 जुलाई 2026 को विश्वविद्यालय परिसर स्थित डॉ. डी.जी.एस. दिनाकरन ऑडिटोरियम में अपना 33वां दीक्षांत समारोह बड़े गर्व और भव्यता के साथ आयोजित किया. समारोह का शुभारंभ करुण्या इनवोकेशन सॉन्ग के साथ हुआ. इसके बाद वाइस चांसलर प्रो. डॉ. एलिजाह ब्लेसिंग ने स्वागत भाषण दिया.

उन्होंने विशिष्ट अतिथियों, स्नातक विद्यार्थियों, अभिभावकों, संकाय सदस्यों और आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया. उन्होंने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए पिछले शैक्षणिक वर्ष में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को रेखांकित किया. इसमें अकादमिक क्षेत्र, शोध, नवाचार, उद्योग सहयोग, विद्यार्थियों की उपलब्धियां और संस्थागत विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रगति शामिल रही. समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के ऑटोमोटिव बिजनेस के अध्यक्ष और महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड, चेन्नई के प्रबंध निदेशक आर. वेलुसामी ने दीक्षांत भाषण दिया.

उन्होंने स्नातक विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उन्हें आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों को स्वीकार करने और समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने वाले नेतृत्वकर्ता बनने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया जीवनभर जारी रहनी चाहिए और विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के समाधान के लिए नवाचार और तकनीक का उपयोग करना चाहिए.

> उन्हें भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में उत्कृष्ट नेतृत्व, उल्लेखनीय योगदान, ऑटोमोटिव नवाचार और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आगे बढ़ाने में उनकी सेवाओं के लिए यह सम्मान दिया गया. दीक्षांत समारोह का समापन खुशी और उत्साह के माहौल में हुआ. इसमें स्नातक विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, संकाय सदस्यों, पूर्व छात्रों और विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया. समारोह ने विद्यार्थियों के जीवन में नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया.

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच सोना-चांदी के दाम में गिरावट

नई दिल्ली, 08 जुलाई. सोने और चांदी की शुरुआत बुधवार को गिरावट के साथ हुई. इससे दोनों का दाम 0.7 प्रतिशत तक कम हो गया. इसकी वजह अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले के चलते मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव बढ़ना है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का 5 अगस्त 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,45,392 रुपए प्रति 10 ग्राम मुकाबले 192 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 1,45,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला. सुबह 10 बजे यह 414 रुपए या 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,44,978 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. अब तक के कारोबार में सोने ने 1,44,800 रुपए का न्यूनतम स्तर और 1,45,356 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है. सोने के साथ चांदी में भी गिरावट देखी गई है. चांदी का 4 सितंबर 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,30,857 रुपए प्रति किलो के मुकाबले 842 रुपए की गिरावट के साथ 2,30,015 रुपए प्रति किलो पर खुला. फिलहाल यह 1,552 रुपए या 0.67 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 2,29,305 रुपए प्रति किलो पर थी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी में बिकवाली देखने को मिली.

ट्रंप के बयान से एशिया में तनाव

सेंसेक्स 1,677 अंक लुढ़का, निफ्टी 516 अंक टूटा

मुंबई, 08 जुलाई. ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को जबरदस्त गिरावट देखी गयी और बीएसई का सेंसेक्स 1,677.12 अंक (2.15 प्रतिशत) लुढ़ककर 76,503.60 अंक पर बंद हुआ.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 516.65 अंक यानी 2.12 प्रतिशत टूटकर 23,882.05 अंक पर आ गया. यह दोनों प्रमुख सूचकांकों का 30 जून का बाद का निचला स्तर है. अमेरिका ने मंगलवार को ईरान पर फिर हमले किये. साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अंतरिम शांति समझौता समाप्त होने की घोषणा की. इससे शेयर बाजारों में जोखिम उठाने की निवेशकों की चाहत को धक्का पहुंचा है. साथ ही कच्चा तेल छह प्रतिशत से अधिक चढ़कर 79 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया.

पीएस लोखंडे उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव नियुक्त

नई दिल्ली, 08 जुलाई. गृह मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के एक महीने के भीतर वापस बुलाये गये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशांत सीताराम लोखंडे को जनसांख्यिकी परिवर्तन हेतु उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीडीसी) में सदस्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के माध्यम से 26 मई को गठित समिति की संरचना में बदलाव किया गया है.

कच्चा तेल की कीमत में 6% आया उछाल

नई दिल्ली, 08 जुलाई. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल कीमतों में बुधवार को 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली. इसकी वजह अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने को माना जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर ताजा हमले के बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर समाप्त हो गया है.

कच्चे तेल के बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का दाम 6.52 प्रतिशत या 4.69 डॉलर प्रति बैरल बढ़कर करीब 80 डॉलर प्रति बैरल के पास पहुंच गया है. डब्ल्यूटीआई क्रूड का दाम 6 प्रतिशत या 4.85 प्रतिशत बढ़कर 75 डॉलर प्रति बैरल हो गया है. नाटो समिट के दौरान अंकारा में बोलते हुए, ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ रात में नए हमले किए. उन्होंने कहा कि ये हमले होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में किए गए थे. उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से, यह सब खत्म हो चुका है. मैं अब उनसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता. वे घटिया लोग हैंज वे बीमार मानसिकता वाले लोग हैं. उन्हें बीमार मानसिकता वाले लोग ही चलाते हैं. वे क्रूर और हिंसक लोग हैं और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता, तो वे उसका इस्तेमाल कर लेते. जहां तक मेरी बात है, यह सब खत्म हो गया है. ट्रंप ने आगे कहा, कि हम कोई समझौता करते हैंज सब सहमत हो जाते हैं.

समाचार विशेष

चुनाव चिन्ह और पार्टी नाम पर घमासान

दोनों गुटों ने चुनाव आयोग को सौंपे दस्तावेज ; फैसले का इंतजार

कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस के दो प्रतिद्वंद्वी गुट ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) मुख्यालय में अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए दस्तावेज जमा किए. असल में तृणमूल के दोनों ही गुट पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना अधिकार जता रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप पार्टी के कोष पर भी अपना दावा कर रहे हैं.

एक ओर, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले 'मूल लेकिन अल्पसंख्यक' गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा व पार्टी की राज्यसभा सदस्य सागरिका घोष स्वयं ईसीआई कार्यालय में अपने दस्तावेज जमा करने पहुंचे. दूसरी ओर, निष्कासित तृणमूल कांग्रेस विधायक ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले 'विद्रोही लेकिन बहुसंख्यक' गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों की एक टीम ने प्रतिनिधिमंडल भेजने के बजाय आयोग की ओर से दस्तावेज जमा किए.

> **ममता गुट ने किया बड़ा दावा**
> हालांकि, स्वयं एक वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने 'मूल लेकिन अल्पसंख्यक' गुट की ओर से दस्तावेज सौंपने के बाद मीडिया से बात की. उन्होंने दावा किया कि कानूनी दृष्टिकोण से जिस गुट का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी स्थिति कहीं अधिक मजबूत है. कल्याण बनर्जी ने कहा कि लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उनका समर्थन कर रही है, इसलिए कुछ भी हो सकता है. इसके बाद, हम इस मामले को अदालत में उठाएंगे और जनता से भी संपर्क करेंगे. अब जबकि दोनों गुटों ने इस मामले में अपने-अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं, गेंद चुनाव आयोग के पाले में है. हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव आयोग का फैसला दोनों गुटों के बीच चल रहे विवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा. चुनाव आयोग के आगामी फैसले से जो भी पार्टी असंतुष्ट होगी, वह निश्चित रूप से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी.

लालू परिवार के कई ठिकाने हो गए

पटना. अभी तक पटना में लालू प्रसाद के परिवार का एक ही ठिकाना होता है. 1990 में जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने उससे पहले ठिकाना उनके भाई का छोटा सा आवास था, जो वेटनरी कॉलेज में था.

उसके बाद मुख्यमंत्री बने तो एक, अणे मार्ग ता पता रहा और मुख्यमंत्री पद गया तो 10, सरकुलर रोड का पता बना. उप मुख्यमंत्री के नाते उनके बेटे तेजस्वी यादव को दूसरा बंगला भी मिला या बड़े बेटे तेज प्रताप को भी दूसरा बंगला मिला, अभी नेता प्रतिपक्ष के नाते भी तेजस्वी को अलग बंगला मिला था लेकिन पूरे परिवार का पता एक ही था और वह था 10, सरकुलर रोड का. लेकिन अब वह लालू परिवार का पता नहीं रहा. अब पूरा परिवार कई जगह बिखर गया. इसका राजनीतिक नुकसान भी होगा. सरकार ने 10, सरकुलर रोड वापस लेने के बाद 39, हार्डिंग रोड का बंगला दिया. लेकिन लालू प्रसाद और राबड़ी देवी अभी कौटिल्य नगर के अपने निजी मकान में शिफ्ट हुए हैं. तेजस्वी यादव एक, पोलो रोड बंगले में रह रहे हैं. तेज प्रताप यादव को भी अलग बंगला मिला हुआ है. तभी अब कहा जा रहा है कि पूरा परिवार एक जगह न रहेगा और न इकट्ठा होगा.

अभी तक खाता नहीं खोल पाई एआईएमआईएम

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं.

इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं. ओवैसी राज्य के अलग-अलग जिलों में जनसभाएं कर रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि वह उत्तर प्रदेश में पूरा गेम बदल देंगे. ओवैसी के इसी बयान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है. ऐसे में सवाल आता है कि क्या सच में एआईएमआईएम यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा उलट फेरकर सकती है? ओवैसी दावे में कितना दम है? और यूपी में एआईएमआईएम कितनी मजबूत है?

यूपी में पहले भी आजमा चुके हैं किस्मत- असदुद्दीन ओवैसी पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी को अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है. इसके बावजूद उन्होंने एक बार फिर पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है. उनकी कोशिश उन विधानसभा सीटों को अपने कब्जे में लेना है, जहां मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं और चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकते हैं.

ओवैसी ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने कैंपेन की शुरुआत बहराइच जिले की मटेरा विधानसभा सीट से की. इसके बाद उन्होंने बिजनौर जिले की नजीबाबाद विधानसभा में भी जनसभा की.

> **नया राजनीति विकल्प बनने की कोशिश**
> ओवैसी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को एक नया राजनीतिक विकल्प मिलना चाहिए. उनका कहना है कि उनकी पार्टी केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए राजनीति करती है. इसी सोच के साथ वह लगातार लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.

विशेष | **योगी के प्लान ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन**

017 दोहराने की तैयारी में भाजपा!

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है. राजधानी लखनऊ में रविवार को एनडीए के सहयोगी दलों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनावी रणनीति, संगठनात्मक समन्वय और भविष्य की सीट शेयरिंग समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक के बाद भाजपा नेतृत्व ने स्पष्ट संकेत दिया कि पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी.

बैठक के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, लेकिन एनडीए के सभी सहयोगी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि गठबंधन के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय के जरिए उत्तर प्रदेश को विकास की नई दिशा देने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए कार्यों का उल्लेख करते हुए भरोसा जताया कि सेवा और सुशासन के आधार पर एनडीए वर्ष 2027 में फिर से सरकार बनाएगा. बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय को प्राथमिकता दी गई. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा और संगठन मिलकर काम करेंगे ताकि 2017 जैसी ऐतिहासिक जीत दोबारा हासिल की जा सके. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता विकास, सुरक्षा और सुशासन चाहती है. उनके अनुसार, राज्य के लोग कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर भाजपा के साथ हैं. भाजपा के लिए 2017 का विधानसभा चुनाव एक बड़ा राजनीतिक मानक माना जाता है, जब एनडीए ने 403 में से 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी. हालांकि 2022 में यह आंकड़ा घटा, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत की. 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा अब संगठनात्मक स्तर पर और अधिक सक्रिय दिखाई दे रही है.

सहयोगी दलों ने दिया जीत का फॉर्मूला- बैठक में शामिल राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि गठबंधन का उद्देश्य सबसे मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारना होगा, चाहे वह किसी भी सहयोगी दल से हो. निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की है.

> **संगठनात्मक मजबूती पर जोर**
> भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी का मजबूत संगठन, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और विकास आधारित राजनीति उसकी सबसे बड़ी ताकत है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता जाति, क्षेत्र और परिवारवाद से ऊपर उठकर संगठन के लिए काम करता है. राजनीतिक जानकारों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि लखनऊ में हुई इस रणनीतिक बैठक का असर आगामी विधानसभा चुनावों में किस रूप में दिखाई देता है और एनडीए का साझा चुनावी फार्मूला कितना प्रभावी साबित होता है.